इंदौर | बुधवार | 1 जुलाई 2026 | वर्ष 66 | अंक 158 | पृष्ठ 20 | मूल्य रु. 6.00
navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

आज डॉक्टर्स डे

नव भारत

राष्ट्र हित का प्रहरी 1934 से

एक नजर में

यमुना एक्सप्रेसवे पर बस-ट्रक टक्कर में 4 की मौत

आगरा. यमुना एक्सप्रेसवे पर राया थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 111 के पास सोमवार देर रात करीब साढ़े तीन बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आगरा से नोएडा की ओर जा रही एक प्राइवेट बस और सामने से आ रहे ट्रक की जोरदार टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 20 से 25 यात्री घायल हो गए हैं. पुलिस के अनुसार, यह हादसा इतना भीषण था कि बस और ट्रक दोनों वाहनों के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस बिहार नंबर की बताई जा रही है, जबकि ट्रक राजस्थान नंबर का है.

जापान की पीएम तीन दिन की यात्रा पर भारत आएंगी

नई दिल्ली. जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर बुधवार को यहां पहुंचेंगी. सुश्री तकाइची की एक से तीन जुलाई तक की यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है. जापानी प्रधानमंत्री एक जुलाई की शाम यहां पहुंचेंगी और गुरूवार सुबह उनका राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जायेगा। इसके बाद वह श्री मोदी के साथ भारत-जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी. इसके बाद दोनों नेता संयुक्त प्रेस वक्तव्य देंगे.

छात्र आत्महत्या रोकने राष्ट्रीय टास्क फोर्स सक्रिय

नई दिल्ली. उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों और आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने मई 2025 से अब तक देश के 10 राज्यों के 30 उच्च शिक्षण संस्थानों का दौरा किया है. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, टास्क फोर्स का उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में मौजूदा परिस्थितियों को समझना और उनके आधार पर प्रभावी नीतिगत सुझाव तैयार करना है. मंत्रालय ने बताया कि एनटीएफ ने अब तक 25 दौर की हितधारक परामर्श बैठकें भी आयोजित की हैं. इन बैठकों का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर बहुआयामी और समावेशी दृष्टिकोण विकसित करना है, ताकि छात्रों की समस्याओं को समझा और समाधान तैयार किया जा सके.

गुस्ताखी माफ

जल सहेजना हमारा दायित्व

सीएम डॉ. मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान का किया समापन

100 दिनों में 3 लाख 63 हजार कार्य कराए गए

20 वर्षों में हमारी सरकारों ने सिंचाई रकबे में की वृद्धि

नवभारत न्यूज

ब्यावरा/ सारंगपुर/राजगढ़ 30 जून, का. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने जल के महत्व को समझा और निरंतर जल संरचनाओं का निर्माण किया.आज हमारा दायित्व है कि हम उन सब का संरक्षण करें एवं उन्हें सहेजें. वे राजगढ़ जिले के भैंसवा माता क्षेत्र में प्रदेश में चलाए गए जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण के समापन कार्यक्रम में बोल रहे थे.

आपने कहा कि जल से ही प्रकृति का उद्भव और जीवन का विकास है. सबसे पहले पृथ्वी पर जलचर आए, जल से ही जीवन है, जल तत्व में सभी तत्व समाहित हैं. हम जब जल संरचनाओं को देखते हैं तो हमारा मन आनंद से भर जाता है. जल संरक्षण और संवर्धन अभियान के तहत मप्र में विगत 100 दिनों में 10 हजार 514 करोड़ की लागत से 3 लाख 63 हजार कार्य कराए गए. इन कार्यों में भरपूर जन समर्थन एवं जन सहयोग मिला है. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि का आधार सिंचाई की सुविधा है. गत 20 वर्षों में हमारी सरकारों ने प्रदेश में सिंचाई के रकबे में तेजी से वृद्धि की है.

(शेष पेज 12 पर)

शिकायत करने में देरी हुई : चंपत

अयोध्या, 30 जून. राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, चंपत राय ने अपने बयान में कहा कि ट्रस्ट को जून के पहले सप्ताह में ही दान राशि में कथित अनियमितताओं की जानकारी मिल गई थी। इसके बाद ट्रस्ट स्तर पर आंतरिक जांच की गई और कुछ नकदी भी बरामद की गई।

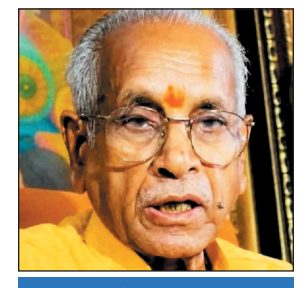

दान चोरी मामले में चंपत राय का बयान रिकॉर्ड

पुलिस अब आरोपियों से करेगी पूछताछ

बयान के दौरान चंपत राय ने कहा कि उन्होंने स्वयं विशेष जांच दल (एसआईटी) को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई। उनके अनुसार, इस दौरान ट्रस्ट अपनी ओर से आंतरिक स्तर पर मामले की जांच करता रहा। पुलिस जांच के अनुसार, 5 जून की एक घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कथित तौर पर बरामद नकदी और उससे जुड़े घटनाक्रम की जानकारी ट्रस्ट को कब और किस स्तर पर मिली थी. मामले में गिरफ्तार आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए पुलिस ने संबंधित अदालत में अनुमति के लिए आवेदन किया है. अनुमति मिलने के बाद आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जांच के दौरान पुलिस ट्रस्ट से जुड़े कई पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस वित्तीय दस्तावेज, बैंक खातों और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रही है। इसके अलावा ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित लगभग 70 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।

> सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान चंपत राय से चढ़ावे के प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशासनिक निर्णय, बैंकिंग प्रक्रिया और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई सवाल पूछे गए। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गिरिबाला और समर्थ की हिरासत अवधि बढ़ी

- जिला अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई
- वायस सैंपल लेने सीबीआई ने कोर्ट से अनुमति मांगी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 30 जून. ट्विशा शर्मा मौत के मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके वकील बेटे समर्थ सिंह की 14 दिन तक न्यायिक हिरासत फिर से कोर्ट ने बढ़ा दी है. बुधवार को जिला अदालत ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए दोनों की हिरासत अवधि बढ़ाई है.

जानकारी के मुताबिक ट्विशा शर्मा के मौत के मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपना पक्ष रखा. मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिए गए. गिरिबाला सिंह और समर्थ के वायस सैंपल लेने के लिए भी सीबीआई ने कोर्ट से अनुमति मांगी है. कोर्ट ने इस पर 3 जुलाई की तारीख सुनिश्चित की है. मिली जानकारी के मुताबिक समर्थ का लैपटाप और मोबाइल फोन सीबीआई ने पहले से ही जब्त कर लिया है. दोनों का पासवर्ड अधिकारियों को नहीं मिलने से जांच में समस्या भी आ रही है. समर्थ के लैपटाप और मोबाइल में जरूरी डेटा मिलने की संभावना जताई जा रही है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह के मकान में चोरी का भी मुद्दा उठाया गया. आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से कहा गया कि पूर्व जज घर पर चोरी हुई है. वकील ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि पूर्व जज को उनके मकान पर लेकर जाया जाए. इससे यह पता चले कि उनके यहां क्या-क्या सामान चोरी हुआ है. इस पर सीबीआई ने आपत्ति जताई और मामले को अलग केस बताया. सीबीआई ने इस दौरान आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग कोर्ट से की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 14 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है.

एमएसएमई सेक्टर को 1 लाख करोड़ की सहायता

- मध्य पूर्व संकट से निपटने के लिए केंद्र ने की मदद
- 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम' शुरू

नई दिल्ली, 30 जून. केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के जरिए मध्य पूर्व संकट से हुए नुकसान से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और अन्य इंडस्ट्रीज को उबारने के लिए एक लाख करोड़ रुपए वितरित किए हैं.

यह जानकारी एमएसएमई सचिव भरत खेरा की ओर से मंगलवार को दी गई. राष्ट्रीय राजधानी में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में बोलते हुए खेरा ने कहा, हमारी कोशिश यह रही है कि मुश्किल समय में एमएसएमई को बेवजह नुकसान न हो. खेरा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से कुछ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट और कैश फ्लो पर असर पड़ा है, लेकिन सरकार ने एमएसएमई को लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल की चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम' शुरू कर दी है. मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की वजह से शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी की समस्या का सामना कर रहे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कैबिनेट ने 5 मई को ईसीएलजीएस 5.0 को मंजूरी दी थी.

> खेरा ने कहा कि सरकार ने संकट से पैदा हुई लॉजिस्टिक्स संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए आय विभाग और शिपिंग अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है. खेरा ने कहा,मेरा मानना है कि हमारा उद्योग स्वभाव से ही बहुत मजबूत और मुश्किल हालात का सामना करने में सक्षम है. चाहे कोविड-19 का समय हो या हाल ही में पश्चिमी एशिया में पैदा हुआ संकट, इसने खुद ही सुधार के उपाय ढूंढे और वैकल्पिक स्रोत तलाशे. आपूर्ति श्रृंखला में आई इन रुकावटों से सीखकर, हमारा एमएसएमई सेक्टर और भी ज्यादा मजबूत और मुश्किल हालात का सामना करने में सक्षम हो गया है.

अब कंपनियां तुरंत घटाएं कीमतें

अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों पर ट्रम्प का बड़ा बयान

वॉशिंगटन/तेहरान, 30 जून. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों से तुरंत ईंधन की कीमतें घटाने की अपील की है.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटकर करीब 68 डॉलर प्रति बैरल रह गई है, लेकिन इसका लाभ अब तक उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है. ट्रम्प ने कहा कि लोग अब भी जरूरत से अधिक कीमत चुका रहे हैं, जबकि कच्चा तेल लगातार सस्ता हुआ है. उन्होंने कंपनियों से पेट्रोल की कीमत करीब 2.50 डॉलर प्रति गैलन तक लाने की अपील की. ट्रम्प ने अपने बयान में कहा कि ग्राहकों से जरूरत से ज्यादा कीमत वसूलना स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनियों ने जल्द कीमतों में कमी नहीं की तो उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

अंतरराष्ट्रीय सोना तस्कर गिरोह से 15 किलोग्राम सोना जब्त

नई दिल्ली, 30 जून. दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 15 किलोग्राम सोना जब्त किया और चार लोगों को गिरफ्तार किया. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और आरोपियों के पास से जब्त किया गया तस्करी का सोना विदेशी मूल का था. खुले बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 21.40 करोड़ रुपये है। यह गिरोह दिल्ली से संचालित हो रहा था.

देश के 26 राज्यों में पहुंच चुका मानसून

नई दिल्ली, 30 जून. दक्षिण-पश्चिम मानसून ने मंगलवार को उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ते हुए जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लिया. देश के 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से जम्मू-कश्मीर तक करीब 1500 किलोमीटर लंबी मानसून ट्रफ (कम दबाव की लंबी पट्टी) सक्रिय हो गई है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में 1 से 4 जुलाई के बीच भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं, अरुणाचल प्रदेश में लेकू नदी के उफान पर आने से असम के जोनाई क्षेत्र में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। देश के कई हिस्सों में मौसम के अलग-अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं. गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा दर्ज की गई, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा.

समीक्षा | प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ की 4 घंटे की मैराथन बैठक

2047 विजन पर पीएम मोदी का फोकस

नई दिल्ली, 30 जून. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ करीब चार घंटे तक चली मैराथन बैठक में सरकार की प्रमुख योजनाओं, उनके क्रियान्वयन और भविष्य की सुधार प्राथमिकताओं की विस्तृत समीक्षा की।

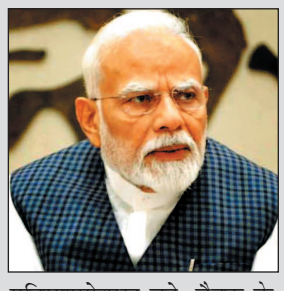

बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी तरीके से आम नागरिकों तक पहुंचे तथा प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पड़ुिरणामोन्मुख बने. बैठक के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा माना जाएगा, जब उनका सकारात्मक प्रभाव लोगों के दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे. उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने पर विशेष बल दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी. (शेष पेज 12 पर)

> केंद्र सरकार द्वारा कई मंत्रालयों, विशेष रूप से रेलवे सहित अन्य विभागों में शुरू की गई 52 सप्ताह में 52 सुधार पहल की प्रगति पर भी चर्चा हुई। इस पहल के तहत सुधारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. बैठक के अंत में प्रधानमंत्री ने सचिवों को निर्देश दिया कि जन-केंद्रित योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई या अनावश्यक देरी न हो.